

# MP shocker: Patients in fields, IV bottles hang from trees

INDO-ASIAN NEWS SERVICE

**Agar Malwa (MP), May 6:** In a shocking sight from Madhya Pradesh, patients in its Agar Malwa district were seen being treated in fields with IV fluid bottles dangling from tree branches.

The increasing number of Covid patients in the district has put a lot of pressure on health care system. Hospitals are overwhelmed with Covid patients and no beds are available. In such a situation, doctors are forced to treat patients wherever they get space. While the corona epidemic wreaks havoc, a large number of patients in the rural areas are suffering from common cold, cough but are not getting tested for Covid. They are not even ready to go to the district headquarters for treatment.

In such a situation, doctors and quacks working in rural areas have found novel ways to treat patients and earn whatever they could.

In the rural areas of Agar Malwa district, patients are being treated in fields with glucose bottles hanging from tree branches, in complete disregard of medical rules. The agricultural fields look like hospital beds and trees have become glucose bottle stands.

Health Officer Manish Kuril says that the action will be taken against doctors who are treating the patients like this.

Tweeting a video of patients being treated in fields, Congress spokesperson Syed Jaffer said: "Agar Malwa is a district which has been under the charge of Chief Minister Shivraj Singh Chouhan. Now look at the pictures."



## **States must implement provisions on right to health, submit report in 4 weeks: NHRC advisory on second Covid wave**

**Anuradha Mascarenhas | Pune |Updated: May 7, 2021 12:55:48 am**

The NHRC had issued a comprehensive set of human rights advisories in September and October 2020, including those related to health and mental health, to protect and promote right to health as guaranteed by Article 21 of the Constitution of India.

The National Human Rights Commission (NHRC) has issued an advisory on right to health in view of the second wave of the Covid-19 pandemic. "We have taken into account ground reports relating to human rights violations, particularly denial of right of access to healthcare, and advised states to implement recommendations and submit reports of the action taken within four weeks," said Bimbadhar Pradhan, secretary general of NHRC.

The advisory was issued on May 4 and, among key recommendations, the rights body said it was the responsibility of a public hospital to transfer the patient to an appropriate hospital if it did not have adequate number of beds for Covid-19 treatment.

Dr Abhay Shukla, member of the core group on health at NHRC, told The Indian Express that a patient, who has tested negative via an RT-PCR test but has symptoms and clinical assessment (X-Ray and CT scan) suggestive of Covid-19, must be treated as a Covid patient.

The NHRC had issued a comprehensive set of human rights advisories in September and October 2020, including those related to health and mental health, to protect and promote right to health as guaranteed by Article 21 of the Constitution of India. According to the NHRC, however, with the advent of the second wave, the situation has worsened and India is now facing a public health emergency of unprecedented proportion and severity.

Hence, it has issued a second advisory on right to health in the context of Covid-19, to protect the human rights of patients and public in general, so as to enable them to effectively access requisite healthcare.

According to the advisory, functional and effective help desks should be set up at all public and private hospitals for preliminary check-up of all incoming patients to assess their need. If a patient is in need of urgent hospitalisation and a bed is not available, then the patient should be handheld to reach a clinical establishment where needed resources are available, the advisory has stated. In no case should the patient and kin be left on their own, the advisory further stated.

It has also stated that each health facility or clinical establishment, treating Covid patients, whether public or private, should prominently display at the entry/reception specific information regarding availability and rates of Covid testing, number of beds of each type and other provisions provided free and/or with regulated cost; and mobile number of the grievance redressal authority or other responsible person to contact in case of any grievance or need for further assistance.

Strategies to augment healthcare workforce availability should be adopted including urgent filling up of existing vacancies, while the body of a deceased Covid-19 patient should be treated with due respect to uphold dignity and handed over to family/caretakers as soon as death is declared, while ensuring that all safety protocols are followed, it stated.

<https://indianexpress.com/article/cities/pune/states-must-implement-provisions-on-right-to-health-nhrc-advisory-on-second-covid-wave-7304989/>

## चेतावनी: मानवाधिकार आयोग ने कहा- कोरोना से जूझ रहा 'स्वास्थ्य तंत्र' दम तोड़ने की कगार पर

जितेंद्र भारद्वाज, अमर उजाला,

पिछले 15 माह से कोरोना के साथ जंग लड़ रहा देश का स्वास्थ्य तंत्र अब किसी भी वक्त जवाब दे सकता है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार इतनी तेज है कि इसके चलते सिस्टम को अपडेट करने का समय भी नहीं मिल पा रहा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केंद्र और राज्यों के लिए जारी अपनी गाइडलाइन यानी 'रामबाण- 5' में इस खतरे से आगाह करने के साथ कई अहम सुझाव दिए हैं।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कोरोना से बचाव के लिए बुधवार को केंद्र एवं राज्यों के लिए एडवायजरी जारी की है। आयोग ने इस पर कार्रवाई रिपोर्ट चार सप्ताह में देने के लिए कहा है। पांच शीर्षकों वाली गाइडलाइन यानी 'रामबाण -5' में केंद्र एवं राज्यों को दर्जनों ऐसे सुझाव दिए गए हैं, जिनकी मदद से देश में रॉकेट गति से फैल रहे कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ी जा सकती है।

क्षमता से ज्यादा कर रहे काम

आयोग ने एडवायजरी में लिखा है कि अस्पताल और स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़े प्रोफेशनल अपनी क्षमता से कहीं आगे जाकर काम कर रहे हैं। देश के हेल्थ केयर ढांचे पर इतना ज्यादा दबाव है कि वह टूटने की कगार पर पहुंच गया है। देश में कोविड-19 की दूसरी लहर ने तबाही मचा रखी है। स्थिति बहुत बुरी है। मौजूदा हालात में खासतौर पर कोरोना संक्रमण की लहर और तीव्रता के मामले में भारत को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जैसा सामना करना पड़ रहा है। मरीजों तक जीवन रक्षक दवाएं और उपकरण पहुंचने में गंभीर खाई नजर आ रही है।

आईसीयू, ऑक्सीजन सप्लाई, जरूरी दवाओं, इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट व दूसरी सेवाओं के मामले में स्थिति अच्छी नहीं है। देश में एक मई तक कोरोना की वजह से मरने वाले लोगों की संख्या 2.12 लाख के पार हो गई थी। देश की जनसंख्या में से अभी तक केवल दो फीसदी लोगों को ही पूर्ण रूप से वैक्सीन लग पाई है।

इन सबके मद्देनजर मरीजों और सामान्य लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए आयोग ने एडवायजरी जारी की है। इसके द्वारा कोरोना संक्रमण को प्रभावी तरीके से रोकने और हेल्थ सिस्टम को अपडेट करने में केंद्र एवं राज्य सरकारों को मदद मिलेगी।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा जारी 'रामबाण- 5'

1. केंद्र और राज्य, इन सिफारिशों को तुरंत लागू करें

केंद्र और सभी राज्यों को मिलकर ऑक्सीजन सप्लाई, जरूरी दवाओं और इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करनी होगी। सरकारों को कोई ऐसी एक व्यवस्था तैयार करनी चाहिए, जहां से हर समय मदद मिलती रहे।

सभी तरह के अस्पतालों में एक हेल्प डेस्क स्थापित किया जाए। यहां पर मरीज को यह पता चलेगा कि उसे अस्पताल में दाखिल होने की जरूरत है या घर पर उसका इलाज हो सकता है। हेल्प डेस्क पर सभी अस्पतालों की सूची लगा दी जाएगी। कहां पर सामान्य बेड है, ऑक्सीजन है या नहीं, आईसीयू बेड, कोविड टेस्टिंग के रेट और दूसरी हेल्थ सेवाओं का ब्यौरा इन हेल्प डेस्क पर रहेगा। देश के सभी राज्यों

एवं जिलों को जोड़कर एक डैश बोर्ड बनाया जाए, जिस पर कोविड को लेकर तमाम तरह की जानकारियां रहेंगी।

बोर्ड पर यह सूचना भी रहेगी कि वेंटिलेटर सुविधा कहां पर है। कालाबाजारी रोकने के लिए दवाओं व इंजेक्शन का रेट तय कर दिया जाए। प्राइवेट अस्पतालों के रिकॉर्ड की नियमित जांच हो, ताकि ये पता चलता रहे कि कोई अस्पताल बेड की संख्या को लेकर गलत जानकारी तो नहीं दे रहा है। ऑक्सीजन सप्लाई, उत्पादन और स्थानीय वितरण प्रणाली को बढ़ाया जाए। इनका वितरण जरूरत के मुताबिक हो।

श्मशान घाट पर ऐसा प्रबंध हो ताकि वेटिंग टाइम कम से कम हो जाए। हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत बनाए रखने के लिए रिटायर्ड स्वास्थ्य कर्मियों की सेवाएं ली जाए। मेडिकल स्टूडेंट जो, ग्रेजुएशन या पीजी में हैं, उनकी सेवाएं कोरोना महामारी में ली जा सकती हैं।

<https://www.amarujala.com/india-news/warning-human-rights-commission-said-health-system-battling-with-corona-is-on-the-verge-of-dying-now-an-expectation-from-ramban-5?pagelid=1>

## बंगाल में केंद्रीय मंत्री के काफिले पर हमला हुआ तो ममता बनर्जी ने उलटा क्या आरोप मढ़ दिया?

पश्चिम बंगाल. 2 मई को विधानसभा चुनाव के नतीजे आए. और तब से ही राज्य के अलग-अलग इलाकों से हिंसा की खबरें आ रही हैं. BJP का दावा है कि 2 मई से लेकर अब तक उसके कम से कम 14 कार्यकर्ता TMC की हिंसा में मारे जा चुके हैं. उधर TMC का आरोप है कि हार से बौखलाई BJP फर्जी वीडियोज़ वायरल करके ममता बनर्जी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है. लगातार हो रही हिंसा की जांच के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने चार सदस्यों की एक टीम बंगाल भेज दी है.

इन सबके बीच बंगाल से हिंसा की दो बड़ी खबरें 6 मई को आईं. पहली घटना पश्चिम मिदनापुर में हुई. यहां बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री वी. मुरलीधरन के काफिले पर हमला हुआ. वहीं दूसरी खबर चंपदनी से आई. यहां TMC की वार्ड कोऑर्डिनेटर और उनके पति पर हमले की खबर है. दोनों पार्टी हमलों के लिए एकदूसरे को जिम्मेदार ठहरा रही हैं.

### केंद्रीय मंत्री के काफिले पर हमला

विदेश राज्य मंत्री वी. मुरलीधरन इस वक्त पश्चिम बंगाल में हैं. 6 मई को उन्होंने ट्वीट किया कि पश्चिम मिदनापुर के पंचकुड़ी में स्थानीय लोगों ने उनके काफिले पर हमला किया. उनकी कार पर पत्थर फेंककर शीशे तोड़ दिए. हमले में केंद्रीय मंत्री को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, हालांकि उनके ड्राइवर को चोट आई. उन्होंने बताया कि काफिले की कई और कारों के शीशे टूटे हैं.

घटना के वक्त केंद्रीय मंत्री के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव राहुल सिन्हा भी मौजूद थे. उन्होंने दावा किया कि मौके पर पुलिसवाले मौजूद थे, इसके बावजूद हमला हुआ. पुलिस का कहना है कि वो घटना की जांच कर रही है.

इस घटना पर बीजेपी के कई नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है.

बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लिखा कि बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है.

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने इसे राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित हिंसा बताया. उन्होंने सवाल किया कि जिस राज्य में मंत्री सुरक्षित नहीं हैं, वहां सामान्य जनता का क्या होगा.

### TMC की महिला कोऑर्डिनेटर और पति पर हमला

पश्चिम बंगाल के चंपदनी इलाके में महिला वार्ड कोऑर्डिनेटर रेखा पासवान और उनके पति रामेश्वर पासवान पर हमला हुआ है. इस विधानसभा सीट पर TMC उम्मीदवार अरिंदम गुई उर्फ बुबाई की जीत हुई है. आरोप है कि इस जीत से बौखलाए भाजपाइयों ने टीएमसी कार्यकर्ता और उनके पति पर बंदूक के कुंदे से हमला किया. आरोप BJP नेता तारक सिंह और उनके सहयोगियों पर है. हमले में कुछ और लोगों के घायल होने की खबर है. सभी का चंदन नगर के महकमा अस्पताल में इलाज चल रहा है.

केंद्रीय मंत्री भड़का रहे हैं हिंसा: ममता

इन दोनों घटनाओं के सामने आने के बाद ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. हिंसा में मरने वाले सभी लोगों के परिवार को दो-दो लाख रुपये का मुआवजा देने का ऐलान किया. इसके अलावा केंद्रीय मंत्रियों पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया. ममता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा,

“मैं देख रही हूँ कि कुछ केंद्रीय मंत्री हिंसा भड़काने के लिए यहां आ रहे हैं, वो भी तब जब राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगी हुई है. चुनावों के बाद इस तरह की घटनाएं हमेशा होती हैं. इसीलिए मैंने घोषणा की थी कि कोई जश्न नहीं मनाया जाएगा. मुझे दोबारा पद संभाले 24 घंटे नहीं हुए और चिट्ठियां भेजी जा रही हैं, केंद्र से टीमों भेजी जा रही हैं. बीजेपी को कूचबिहार में ज्यादा सीटें मिली हैं, इसलिए वो लोग वहां अति मचा रहे हैं.”

पश्चिम बंगाल में लगातार हो रही हिंसा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 3 मई को राज्य के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी थी. हिंसा को लेकर रिपोर्ट मांगी थी. लेकिन बंगाल की तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं भेजी गई. 5 मई को ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री के तौर पर तीसरी बार शपथ ली. उनके शपथ लेने के कुछ घंटों के अंदर ही गृह मंत्रालय के सचिव अजय भल्ला की तरफ से बंगाल सरकार को एक और चिट्ठी भेजी गई. इसमें लिखा गया,

“मैं आपको याद दिला दूँ कि चुनाव के बाद हो रही हिंसा को लेकर मैंने 3 मई को डिटेल मांगी थी, लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं भेजी गई है. इस दूसरी चिट्ठी के जवाब नहीं मिलने को गंभीरता से लिया जाएगा.”

अजय भल्ला ने पत्र में बंगाल के मुख्य सचिव से पूछा कि हिंसा को रोकने के लिए पर्याप्त कदम अभी तक क्यों नहीं उठाए गए. हिंसा जारी है. इसे रोकने के लिए तुरंत कदम उठाए जाएं और रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी जाए.

इसके अलावा गृह मंत्रालय ने एडिशनल सेक्रेटरी रैंक के एक अधिकारी की अध्यक्षता वाली चार सदस्यीय समिति भी बनाई है. ये समिति बंगाल में हो रही हिंसा की जांच करेगी.

इसके अलावा, बंगाल में हिंसा पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी संज्ञान लिया है. NHRC ने जांच के लिए टीम बनाने के निर्देश दिए हैं. टीम को घटनास्थल पर जाकर साक्ष्य जुटाने के निर्देश दिए गए हैं.

<https://www.thelallantop.com/news/west-bengal-post-poll-violence-union-minister-convoy-attacked-in-west-midnapore-tmc-coordinator-attacked-in-champdani/>

## **Unbecoming for West Bengal Governor to bring up post-poll violence at Mamata Banerjee's swearing in ceremony**

**Arun Srivastava**

West Bengal Governor Jagdeep Dhankar has the reputation of behaving like a BJP leader and adopting a confrontationist attitude towards Mamata Banerjee and her government

Goebbelsian tactics seem to have come alive in West Bengal with the RSS and BJP pushing a divisive narrative that the state has been in the midst of a 'communal war' like situation.

Coinciding with the occasion of the swearing in of Mamata Banerjee as chief minister, two more events took place. One that took place in Raj Bhawan was more politically noteworthy.

Going beyond the constitutional practices and norms, just after the swearing ceremony, Governor Jagdeep Dhankar used the occasion to tell Mamata that he was extremely concerned at reports of post poll violence.

Dhankhar sent out a sharp message to her on the issue. "In our Constitution, the law has the highest position and we should maintain that. We should immediately take necessary action and send relief to the victims' families. I have every hope that the Chief Minister on an urgent basis will take all the steps to restore the rule of law".

The oath was administered at a low-key ceremony at Raj Bhawan held amid the raging COVID pandemic. The Left Front and the BJP boycotted the ceremony.

Dhankhar said such senseless violence shames democracy. Such collapse of law and order will neither be overlooked nor allowed, he said, adding that the Prime Minister had called him up and expressed his serious anguish and concern at the alarmingly worrisome law & order situation.

Dhankar has the reputation of behaving like a BJP leader and adopting a confrontationist attitude towards Mamata and her government. But using this solemn occasion was deprecated not only by the political circles but even by the people of the state. It was perceived as a naked attempt by the BJP leadership to humiliate her.

On her part, Mamata did not take it lying low. She said that for three months the Election Commission was running the state administration and it was the EC's responsibility to check the violence.

Mamata said after being sworn in, "My first priority is to control COVID. I am now going to Nabanna (state administration headquarter). There I will hold a meeting with my officers and will take necessary measures to control COVID immediately. I will address media again this evening."

"There is some sporadic violence after the election. We have to control that with a strong hand. In the last two months, the administration system was run by the Election



Commission. There was some inefficiency. We have to change the whole setup immediately,” she further added.

Mamata Banerjee contended that that violence and clashes were taking place in those areas where the BJP had won the elections and most of the videos of violence being shared on social media were either fake or old.

She said: "I have noticed that violence and clashes are taking place in those areas where the BJP has won the elections. These places can be seen as black spots. Barring some sporadic incidents, most were fake. BJP is showing old videos."

She even said to the BJP “You have been torturing people since the elections and now, stop this. Or else, law will take its course. “

Even after being aware that EC has been responsible for running the state administration, the Home Ministry has written to the state government accusing it of not taking steps to stem the violence and asked why a report sought by it has not been submitted yet.

The Home Ministry has asked the state government to take all measures necessary to stop the violence. “The letter has also said that if the situation report is not received at once, it will be viewed seriously,” an official said.

Incidentally, the state BJP, which has already launched a vitriolic campaign against Mamata on the alleged escalation of violence, organised an oath taking ceremony against 'Politics of Hate' in the presence of its national president JP Nadda at its office in Calcutta.

It is noteworthy that even as the polling process was on, BJP leaders including UP Chief Minister Yogi Adityanath had threatened the TMC cadres to wait till May 2, the day of the counting, after which the TMC workers would be thrashed.

Its state chief Dilip Ghosh had warned them to get ready for ‘treatment’. Its national general secretary Rahul Sinha opined that in Shitalkuchi the CISF should have killed 8 TMC cadres instead of gunning only four. Other senior BJP leaders too have been going around threatening the TMC workers.

Intriguingly, its senior leader Swapan Dasgupta, a fairly senior journalist who had held many senior positions in the media before joining politics, tweeted that thousands of Hindus are taking shelter in open fields in Birbhum district. In his enthusiasm to serve the divisive politics of his bosses, he even ignored the basic tenet of journalism to check and cross check.

The incident was denied by the police.

It indeed came as a surprise that people who were engineering violence were taking ‘oath’ against ‘politics of hatred’. All the newly elected BJP legislators took an oath against 'politics of hate'. Nadda in his address to the MLAs told that the ‘oath-taking’ by BJP MLAs was a mark of respect to accept the people's mandate in the West Bengal elections and also highlight post-poll violence allegedly by TMC goons.

Nadda also stated that the opposition is boycotting Mamata Banerjee's oath-taking ceremony to protest against the violence. In addition, he said that the saffron party will 'dismantle' political violence in West Bengal.

Incidentally, besides the Home Ministry, National Human Rights Commission (NHRC), the National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) and the National Commission for Women (NCW) too have also raised concerns over the violence and sought an inquiry.

<https://www.nationalheraldindia.com/opinion/unbecoming-for-west-bengal-governor-to-bring-up-post-poll-violence-at-mamata-banerjees-swearing-in-ceremony>

## बंदियों को कोरोना से खतरा आयोग ने मांगी है रिपोर्ट

**भोपाल।** मानव अधिकार आयोग बंदियों को लेकर चिंतित है। आयोग के मुताबिक प्रदेश की जेलों में 300 बंदी कोरोना से संक्रमित हैं। ऐसे में आयोग ने अन्य 8 हजार बंदियों को कोरोना संक्रमण से बचाने के संबंध में जेल महानिदेशक से जांच रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने पूछा है कि संक्रमित बंदियों से अन्य बंदियों को बचाने के लिए जेल प्रशासन किस तरह के उपाय कर रहा है। आयोग ने जानकारी मांगी है कि बंदियों को वैक्सीन लगी है या नहीं। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस नरेंद्र कुमार जैन ने डीजी जेल से 18 मई तक रिपोर्ट मांगी है। प्रदेश की जेलों में 8 हजार में से 4500 बंदियों को पैराल पर छोड़ा गया है। फिर भी बंदियों की संख्या कम नहीं हो रही। ऐसे में आयोग ने कोरोना से बचाने के संबंध में जेल व्यवस्था से संबंधित जानकारी मांगी है।

## कहां गुम हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच और मानवाधिकार की वकालत करने वाले: नड्डा

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल में केंद्रीय मंत्री वी. मुरलीधरन के काफिले पर हमले की घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि जब राज्य से हजारों लोग जान बचाने के लिए पलायन कर रहे हैं, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, तब फ्रीडम ऑफ स्पीच और मानवाधिकार की वकालत करने वाले गायब है। नड्डा ने गुरुवार को ट्वीट कर कहा, हूँ पश्चिम मिदनापुर में केंद्रीय मंत्री वी. मुरलीधरन जी के काफिले पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया हमला बहुत ही निंदनीय है। मैंने कल ही कहा था कि बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। जहाँ भारत सरकार के मंत्री पर हमला हो जाय, वहाँ आम जनता की क्या स्थिति होगी? हूँ भाजपा अध्यक्ष ने आगे कहा, हूँ चुनाव परिणाम आने के बाद से पूरे पश्चिम बंगाल में टीएमसी प्रायोजित हिंसा चरम पर है। लगातार भाजपा कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमले हो रहे हैं। जब हजारों लोग जान बचाने के लिए पलायन कर रहे हैं, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, तब फ्रीडम ऑफ स्पीच और मानवाधिकार की वकालत करने वाले गायब है। हूँ उल्लेखनीय है कि पश्चिमी मिदनापुर के ग्रामीण इलाके में केंद्रीय मंत्री मुरलीधरन के काफिले पर हमला हुआ। हालांकि, इस हमले में मंत्री और उनके साथ के लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं।

**NHRC takes cognizance of  
alleged Post-poll violence**

The National Human Rights Commission, NHRC, India has come across several media reports published in various newspapers regarding death of some persons in the alleged Post-poll violence in West Bengal on May 3.

The political workers allegedly clashed with each other, party offices were torched down and some homes were ransacked and valuables also looted.

Considering as a fit case of alleged violation of Right to Life of the innocent citizens, the Commission has today taken suo-motu cognizance of the matter and has requested its DIG (Investigation) to constitute a team of the officers of the Investigation Division of the Commission to conduct an on the spot fact finding investigation and to submit a report.

**NHRC asks UP Government to  
release innocent person**

The National Human Rights Commission, NHRC India, having not received any response from the Government of Uttar Pradesh to its show cause notice in the matter of the arrest and imprisonment of a person on mistaken identity, has recommended to the State through its Chief Secretary that action should be taken for the release of the victim with dignity and he should be paid Rs three lakh as relief for violation of his human rights.

**Justice PC Pant, Member, NHRC  
appointed as its Acting Chairperson**

President of India has authorised Justice Prafulla Chandra Pant, Member, National Human Rights Commission, NHRC India, to act as its Chairperson.

Prior to his appointment as Member, NHRC on April 22, 2019, he was a Judge of the Supreme Court from August 2014 to August, 2017. He has studied law at the Lucknow University.

## Hours After Mamata Banerjee Takes Charge, A Home Ministry Warning

Both the BJP and the Left have slammed the Trinamool Congress and accused it of attacking their workers amid victory celebrations after the May 2 results.

New Delhi: On a day West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee was sworn in for a third term after a decisive win against the BJP, the Union Ministry of Home Affairs shot off another letter to the state government asking why it had not written back about measures taken to stop the violence after Sunday's election result.

"I remind you that no report has been submitted despite my asking for details on post-poll violence on May 3rd. Non-compliance of this second letter would be taken seriously," Union Home Secretary Ajay Bhalla said in the second letter dispatched to state government two days after he wrote the first letter.

Mr Bhalla also asked the West Bengal Chief Secretary why adequate measures to stop the violence have not been taken so far. "There are fresh reports which suggest that post-poll violence has not stopped. Immediate measures should be taken to stop violence and report regarding the same should be sent immediately," he wrote.

A four-member team of the Home Ministry, headed by an Additional Secretary, has been sent to West Bengal to assess the ground situation, government officials said.

The National Human Rights Commission (NHRC) on Wednesday also took note of the post-poll violence that erupted in West Bengal after assembly election results were announced on May 2. The human rights body had requested its Deputy Inspector General (Investigation) to constitute a team to look into the matter. The team has been asked to conduct an on-the-spot fact-finding investigation and submit it in two weeks.

"Considering as a fit case of an alleged violation of Right to Life of the innocent citizens, the Commission has today taken suo-moto cognizance of the matter and has requested its DIG (Investigation) to constitute a team of the officers of the Investigation Division of the Commission to conduct an on the spot fact-finding investigation and to submit a report at the earliest, preferably within two weeks," the NHRC said.

Several other human rights bodies such as the National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) and the National Commission for Women (NCW) have also raised concerns over reports of violence and sought an inquiry.

Both the BJP and the Left have slammed the Trinamool Congress and accused it of attacking their workers amid victory celebrations after the May 2 results.



The Trinamool Congress and the West Bengal Police have rebuffed most of the charges saying a large number of fake videos and images from older incidents were being spread on social media.

On Tuesday, BJP National President JP Nadda visited Bengal to meet the families of the victims assuring that justice will be served democratically. "Mamata ji, what your party has done after victory, shows how much you and your party workers believe in democracy. The TMC workers and the politician are claiming that the clips of these incidents doing the rounds on social media are nothing but fake news. I would like to request the media to tell the truth to the nation," said Mr Nadda.

Trinamool Congress leaders said they had nothing to do with any such incidents and urged people to maintain peace and follow COVID-19 protocols.

<https://www.ndtv.com/india-news/bengal-warned-of-stern-action-in-2nd-home-ministry-letter-over-violence-2429827>

## **Home Ministry warns Bengal govt in 2nd letter, asks why post-poll violence has not stopped**

In his second letter to the Bengal government, the Union Home Secretary Ajay Bhalla reminded it that no report has been submitted to him despite asking for details on the post-poll violence on May 3.

The Ministry of Home Affairs on Wednesday wrote another letter to the West Bengal government asking why it had not written back about measures taken to stop the violence in the state that erupted after Sunday's Assembly election result. The BJP shot the letter on a day when Mamata Banerjee was sworn in as the Chief Minister of West Bengal for the third consecutive term.

In his second letter to the Bengal government, the Union Home Secretary Ajay Bhalla reminded it that no report has been submitted to him despite asking for details on the post-poll violence on May 3.

Bhalla also asked the West Bengal Chief Secretary why adequate measures to stop the violence have not been taken so far. There are fresh reports which suggest that post-poll violence has not stopped. Immediate measures should be taken to stop violence and report regarding the same should be sent immediately, he wrote.

The National Human Rights Commission (NHRC) on Wednesday also took suo-moto cognizance of the Bengal post-poll violence.

Considering as a fit case of an alleged violation of Right to Life of the innocent citizens, the Commission has today taken suo-moto cognizance of the matter and has requested its DIG (Investigation) to constitute a team of the officers of the Investigation Division of the Commission to conduct an on the spot fact-finding investigation and to submit a report at the earliest, preferably within two weeks, the NHRC said.

However, the Trinamool Congress and the West Bengal Police have denied most of the charges saying a large number of fake videos and images from older incidents were being circulated on social media.

Mamata Banerjee won a landslide victory in the Bengal election to secure a third straight term. The Trinamool won 213 of 292 seats while its strongest rival, BJP, finished second with 77 seats.

<https://www.apnlive.com/home-ministry-bengal-govt-post-poll-violence/>

## **I remind you....MHA's stern warning to West Bengal on post-poll violence**

New Delhi, May 06: The Union Home Ministry has warned the Bengal government following the wide-spread violence that broke out in the state post the elections.

Union Home Secretary Ajay Bhalla sought to know why the government had not written back about the measures taken to stop the violence. He further said, "I remind you that no report has been submitted despite my asking for details on post-poll violence on May 3rd. Non-compliance of this second letter would be taken seriously."

He also asked the Chief Secretary of the state why measures had not been taken to stop the violence. "There are fresh reports which suggest that post-poll violence has not stopped. Immediate measures should be taken to stop violence and report regarding the same should be sent immediately," he said. On Wednesday the National Human Rights Commission requested its Deputy Inspector General (Investigation) to conduct an on the spot fact finding investigation and submit it in two weeks.

Considering as a fit case of an alleged violation of Right to Life of the innocent citizens, the Commission has today taken suo-moto cognisance of the matter and has requested its DIG (Investigation) to constitute a team of the officers of the Investigation Division of the Commission to conduct an on the spot fact-finding investigation and to submit a report at the earliest, preferably within two weeks," the NHRC said.

<https://www.oneindia.com/india/i-remind-you-mha-s-stern-warning-to-west-bengal-on-post-poll-violence-3255292.html>

## **Who's Safe In WB?: Javadekar Alleges State-sponsored Terror As MoS Muraleedharan Attacked**

Shortly after Union Minister Muraleedharan's convoy was attacked in Bengal, Union Minister Prakash Javadekar demanded strict & strong action against violence

Shortly after Union Minister V Muraleedharan's car was attacked in West Bengal's Panchkhudi by TMC goons, Union Minister Prakash Javadekar while addressing a press conference on Thursday said that whatever happened in the state is "absolutely shocking". Speaking about the attack on his Ministerial colleague, Prakash Javadekar said that anything could have happened.

Union Minister Prakash Javadekar said, "If Ministers can be attacked then who is safe in Bengal? It is a state-sponsored terrorism, state-sponsored violence aimed at BJP workers and voters. Due to this post-poll violence, thousands of BJP workers had to flee from their house to take shelter elsewhere. They have been beaten. So far 14 workers have been murdered and over 1,000 houses have been burnt in this post-election violence by TMC."

Calling the current violence in Bengal an "unprecedented violence post-election" that India has witnessed, Javadekar said that the Centre not only condemns this but also demands strict and strong action against this "worst kind of violence". Stating that this kind of poll violence has shamed democracy norms of the country, he said, "This shows that what Mamata Banerjee was speaking during campaigning that after election results, all the security forces will go and then it will be only TMC is what is actually happening in the state currently."

Bengal: TMC goons attack Union Min Muraleedharan's car

Earlier during the day, Union Minister V Muraleedharan's car and convoy were attacked in Bengal's Panchkhudi. After this incident, the Union Minister took to his official Twitter handle and alleged that the attack was perpetrated by Trinamool Congress (TMC). Informing that the TMC goons had attacked his convoy in West Midnapore by breaking windows and attacking personal staff, Muraleedharan said that he is cutting short his trip due to this.

This latest development comes after the Ministry of Home Affairs (MHA) on Thursday sent a 4-member team to look into the post-poll violence in West Bengal. The Centre's team was expected to take stock of the ground situation in the state and then send a report to the government within 48 hours.

Earlier on Wednesday, the MHA had dialled the West Bengal Chief Secretary for a report on the disorder and warned to take the matter seriously if a report was not

furnished immediately. The Home Ministry had first sought a report from the Mamata Banerjee-led government on May 3 after incidents of attacks on workers of the opposition parties began surfacing following TMC's thumping victory in the assembly polls.

#### Post-poll violence in West Bengal

After the Trinamool Congress recorded a landslide victory in West Bengal, political violence gripped the state with its workers running rampage and engaging in anarchy in the name of 'victory celebrations.' Both the BJP and the Left have confirmed reports of attacks on their party cadre. The saffron party has also alleged that the miscreants were torching the houses and damaging the properties of BJP leaders who had contested the polls.

On May 5, as Mamata Banerjee took oath as the Chief Minister for her third consecutive term, the BJP boycotted her swearing-in ceremony taking an oath against 'politics of hate' instead. Gathering at the Hastings Election office, BJP MLAs along with party president JP Nadda assured that the saffron party will 'dismantle' political violence in the state. Nadda who concluded his 2-day visit to Bengal had also visited houses of the party workers who had been targeted in the days subsequent to the May 2 result.

Several human rights bodies such as the National Human Rights Commission (NHRC), the National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) and the National Commission for Women (NCW) have also raised concerns over the violence in the Mamata Banerjee-ruled state and sought an inquiry.

<https://www.republicworld.com/india-news/politics/whos-safe-in-wb-javadekar-alleges-state-sponsored-terror-as-mos-muraleedharan-attacked.html>

## **MHA forms four-member team to probe post poll violence in West Bengal**

NEW DELHI: Having received no response from the West Bengal government to its May 3 letter seeking immediate measures to check post-poll violence in the state and asking for a detailed report on the incidents, the ministry of home affairs (MHA) on Thursday sent a four-member team of officers to the state to assess the ground situation.

The team, led by an additional secretary in MHA, was deputed a day after the ministry sent a reminder to the West Bengal chief secretary asking it to furnish the report on the targeted post-poll attacks “at once”, failing which “the matter will be viewed seriously”.

Sources said the MHA team, which comprises a senior CRPF officer, left for Kolkata on Thursday morning.

While the West Bengal government is expected to cooperate with the Central team, make information available as well as facilitate its visit on the ground, there have been instances in the distant past where such teams sent by the home ministry had to counter non-cooperation upon reaching the state, in the form of being made to wait at the airport at the destination and not being provided police protection. There have also been rare cases of such teams having to return from the airport of the destination state.

In a communication sent to the West Bengal chief secretary on Wednesday, the home ministry had recalled its letter dated May 3 seeking a detailed report on post-poll incidents and said: “Unfortunately no response has been received from the government of West Bengal....till date. As per reports, there is no let-up in post-poll violence. It is evident that no effective measures have been taken by the state government so far to contain violence.”

The chief secretary was asked by MHA to ensure that all the necessary steps to prevent incidents of political violence are taken without further loss of time and a detailed report on these incidents is furnished to the Centre “at once”.

Incidentally, given the Constitutional scheme of things and the strong federal set up, the Centre can make only few interventions given that law and order is an exclusive domain of the state government. The options for the Centre include sending advisories, calling for reports from the chief secretary on law and order situations and sending a team of officers to assess these situations for itself.

The state is expected to cooperate with the Central team, make information available as well as facilitate its visits on the ground.

Meanwhile, rights bodies like NHRC and NCW have already taken note of the post-poll attacks in West Bengal and swung into action. On Tuesday, NHRC took suo-motu cognizance of media reports relating to the post-poll attacks in West Bengal and asked its director (investigation) to constitute a team for conducting an on-the-spot, fact-finding inquiry and submit a report, possibly within the next fortnight. Even the National Commission for Women issued a notice to the state DGP seeking immediate action in case relating to post-poll attacks on women.

This is not the first time that the Mamata Banerjee government has defied the Centre on matters relating to political violence in the state. After BJP president J P Nadda's convoy was attacked in December, the home ministry had summoned the state chief secretary and DGP to New Delhi for a "discussion on law and order", but the latter two never turned up, saying that the issue was already being addressed with "utmost seriousness". Even the home ministry's request for sending three West Bengal cadre IPS officers – linked to laxity that led to the attack on Nadda -- on Central deputation was not honoured by the state government.

<https://timesofindia.indiatimes.com/india/mha-forms-four-member-team-to-probe-post-poll-violence-in-west-bengal/articleshow/82425632.cms>